Introduction of Textiles Modernisation Fund

556. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the sluggish trend in textile exports and lack of competitive position of the clothing industry;

(b) if so, the measures proposed to be taken to ensure that during 1997-98 textile export targets should be more than 1995-96 exports which amounted to $ 10,685 million, equivalent to Rs. 35,526 crore; and

(c) whether Government have now reintroduced the Textiles Modernisation fund (TMF) Scheme to meet modernisation and technological needs of the industry; if so, when?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R. L. JALAPPA): (a) to (b) There has been a sluggish trend in textile exports in some sub-sectors only. However, the sub-sectors of readymade garments, cotton textiles and woollen textiles have shown positive growth.

The overall target for exports of textiles for 1997-98 is likely to be fixed at a higher level than the actual exports of 1995-96.

(c) A proposal is under consideration to facilitate modernisation, through technological upgradation of the Textile Industry.

राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजनाएं

557. श्री अजीत जोगी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं, जिनमें राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(घ) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है तथा इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) वर्ष 1994-95 के दौरान, विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत जल संसाधन मंत्रालय की मूल्यांकन समिति द्वारा गुजरात (7), कर्नाटक (1) तथा राजस्थान (8) राज्यों की 16 उप परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था। तथापि, विश्व बैंक द्वारा इन उप परियोजनाओं को मंजूर नहीं किया गया था। राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना 31.3.1995 से बंद है।

(ख) राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना में दस राज्यों नामशः आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश ने भाग लिया।

(ग) सहभागी राज्यों में साँझुदा चुनिन्दा सिंचाई प्रणालियों के निष्पादन में सुधार के लिए जून, 1987 में राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना को शुरू किया गया था। (घ) और (ङ) नीचे राज्यवार विवरण दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय जल प्रबंधन **परियोजनाएं (1989—95)**

क्रम सं॰ राज्य	उप परियोजनाओं की संख्या	कृष्य कमान क्षेत्र (000 हैक्टेयर)	मूल अनुमानित लागत (लाख रु॰)	मार्च, 95 तक संचयी व्यय (लाख रु॰ में)	3/95 तक पूरी की गई स्कीमों की सूचना		
					संख्या	कृष्य कमान क्षेत्र (000 हैक्टे॰)	व्यय (लाख रु॰ में)
1. आंध्र प्रदेश	10	243	6130	4578	5	48	2040
2. कर्नाटक	34	368	8581	10001	18	206	7880
3. तमिलनाडु	14	222	6297	11855	7	75	2750
4. केरल	5	49	1399	1734	5	49	1950
5. बिहार	2	167	4141	678	—	—	—
6. मध्य प्रदेश	20	277	7871	4867	8	77	2520
7. उत्तर प्रदेश	2	1489	6164	740	—	—	—
8. उड़ीसा	8	109	3409	1155	—	—	—
9. हरियाणा	1	340	11200	10657	1	340	10660
10. गुजरात	2	20	753	62	—	—	—
कुल	98	3284	55945	46327	44*	795	27800

*कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई शेष 54 स्कीमें पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।